

**राजस्थान-सरकार**  
**मत्स्य विभाग की लाभकारी योजनाएं**  
**सेन्ट्रल सेक्टर योजना-नीली क्रांति**

**अन्तर्देशीय मत्स्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता**

- 1 मछली पालन हेतु निजी भूमि पर नवीन तालाब निर्माण  
इकाई लागत राशि रुपये 7 लाख प्रति हैक्टयर जल क्षेत्र  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत अधिकतम।
- 2 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार  
इकाई लागत राशि रुपये 3.50 लाख प्रति हैक्टयर  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत अधिकतम।
- 3 मत्स्य हैचरी 10 मिलियन फ़ाई प्रति वर्ष की क्षमता  
इकाई लागत राशि रुपये 25 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत अधिकतम।
- 4 फिश फीड इकाई की स्थापना  
1 से 5 क्विंटल प्रतिदिन क्षमता  
इकाई लागत राशि रुपये 10 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत अधिकतम।
- 5 कौशल विकास  
प्रशिक्षण निःशुल्क  
प्रशिक्षण भत्ता रुपये 300 प्रतिदिन  
यात्रा भत्ता रुपये 100 अधिकतम  
भोजन/नाश्ता भत्ता रुपये 100 प्रतिदिन

**समुद्री मछली का विकास**

- 1 मीठे (ताजा) पानी में मोती पालन:-  
इकाई लागत राशि रुपये 25 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत अधिकतम।

**मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता**

- 1 सेविंग कम रिलीफ योजना  
सक्रिय मछुआरा सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 9 माह में कुल रुपये 1500 का योगदान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुल रुपये 3000 का योगदान निषेध ऋतु (3 माह) के दौरान प्रतिमाह रुपये 1500 का मछुआरों को भुगतान
- 2 मछुआरों के लिए आवास सुविधा  
इकाई लागत राशि रुपये 1.20 लाख प्रति आवास  
20 आवास समूह हेतु एक ट्यूब वेल राशि रुपये 50 हजार  
75 आवास समूह हेतु एक सामुदायिक केन्द्र राशि रुपये 4 लाख सम्पूर्ण राशि का केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन

### 3 सक्रिय मछुआरों का दुर्घटना बीमा

प्रिमियम का केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन  
मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई विकलांगता पर बीमित राशि रूपये 2.00 लाख का भुगतान  
आंशिक स्थाई अपंगता पर बीमित राशि रूपये 1.00 लाख का भुगतान  
चिकित्सा पर अधिकतम राशि रूपये 10 हजार तक का पुनर्भरण

## पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

### 1 आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

इकाई लागत रू0 2.50 लाख प्रति टन अधिकतम राशि रूपये 50 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 2 रिटेल फिश मार्केट हेतु आधार भूत सुविधाओं का विकास

इकाई लागत राशि रूपये 100 लाख 10 दुकानों के लिये  
इकाई लागत राशि रूपये 200 लाख 20 दुकानों के लिये  
इकाई लागत राशि रूपये 500 लाख 50 दुकानों के लिये  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 3 मोबाईल/रिटेल आउटलेट (कियोस्क) की स्थापना

इकाई लागत रूपये 10 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 4 रेफ्रिजरेटेड ट्रक/कन्टेनर 10 टन क्षमता युक्त

इकाई लागत रूपये 25 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 5 इन्सूलेटेड ट्रक 6 टन क्षमता युक्त

इकाई लागत रूपये 15 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 6 आटोरिक्षा मय आईस बॉक्स

इकाई लागत रूपये 2 लाख  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 7 मोटर साईकिल मय आईस बॉक्स

इकाई लागत रूपये 60 हजार  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

### 8 साईकिल मय आईस बॉक्स

इकाई लागत रूपये 3 हजार  
अनुदान सामान्य 40 प्रतिशत, एस.सी. व एस.टी. सभी महिलाएं व सहकारी संस्थाएं 60 प्रतिशत  
अधिकतम।

मछली पालन तथा प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु मत्स्य विभाग के स्थानीय कार्यालयों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जाकर अपने प्रस्ताव संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।